बिहार राज्य होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, पटना

बनाम

बिहार राज्य और अन्य **10** अक्टूबर **1995**

सुजाता वी. मनोहर, जे.

अपील स्वीकृत।

प्रस्तुत अपीलें बिहार राज्य होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड, पटना (इसके बाद बोर्ड के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर की गई हैं। बोर्ड का गठन बिहार होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली विकास अधिनियम 1953 के तहत किया गया है। विवाद होम्योपैथिक चिकित्सकों के 8 पदों को समाप्त करने से संबंधित है, जिनमें से 6 पदों पर तीन रिट याचिका संख्या 4462 में छह याचिकाकर्ताओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1988 का 4039 और 7424 पटना उच्च न्यायालय में दायर किया गया। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश, जिन्होंने इन रिट याचिकाओं पर सुनवाई की, ने कहा कि पदों को कानून के अनुसार समाप्त नहीं किया गया था क्योंकि प्रतिवादी यानी जिस बोर्ड ने इन पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था, उसका विधिवत गठन नहीं किया गया था। इस फैसले को पटना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपील में बरकरार रखा है। इस निर्णय से, वर्तमान अपीलें हमारे समक्ष दायर की गई हैं। रिट याचिकाओं में छह याचिकाकर्ताओं को 1983–1984 के आसपास अस्थायी/तदर्थ आधार पर होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 1985 में उनकी नियुक्तियाँ नियमित कर दी गईं। इस अवधि के दौरान बोर्ड गंभीर वित्तीय बाधाओं से जूझ रहा था। जवाबी हलफनामे में यह बताया गया है कि 22.11.1975 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार, अपीलकर्ता–बोर्ड को परीक्षा आयोजित करने और डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने की अपनी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित बोर्ड के काम का एक बड़ा हिस्सा बिहार विश्वविद्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया। अपीलकर्ता–बोर्ड के कर्तव्यों में कटौती के कारण, बोर्ड का मौजूदा स्टाफ भी बोर्ड की आवश्यकता से अधिक था। इतने अतिरिक्त स्टाफ होने के बावजूद, छह और नियुक्तियाँ की गईं, जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिकाओं में छह याचिकाकर्ताओं को होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया। अपीलकर्ता–बोर्ड के अनुसार, इससे बोर्ड पर अनावश्यक वित्तीय दायित्व आ गया जो पहले से ही वित्तीय दबाव में था। दरअसल, 1978 में

ही बोर्ड के अध्यक्ष ने बोर्ड के कम कार्यभार को देखते हुए सरकार से बोर्ड के अतिरिक्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य निदेशालय में समायोजित करने का अनुरोध किया था। यह अनुरोध 1983 में दोहराया गया था। ऑडिट रिपोर्ट में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति और ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने पर कुछ आपत्तियां उठाई गईं। अंततः बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने अन्य बातों के साथ–साथ निर्देश दिया कि अपीलकर्ता–बोर्ड के वित्तीय बोझ पर नियंत्रण रखने के लिए, कोई नया पद सृजित नहीं किया जाना चाहिए और कोई नया व्यय नहीं किया जाना चाहिए। एक और निर्देश दिया गया कि अनावश्यक पदों को समाप्त किया जाये और अनियमित नियुक्तियों को रद्द किया जाये। इसलिए, अपीलकर्ता–बोर्ड ने 14 मई, 1988 को एक बैठक बुलाई, जिसमें उसने होम्योपैथिक चिकित्सकों के 8 पदों को समाप्त करने का एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा रखे गए छह पद भी शामिल थे। अपीलकर्ता–बोर्ड के 14 मई, 1988 के संकल्प को इन रिट याचिकाओं में संशोधन के माध्यम से चुनौती दी गई थी क्योंकि रिट याचिकाएं दायर होने के बाद संकल्प पारित किया गया था। रिट याचिकाएँ मूल रूप से वेतन के भुगतान और अन्य राहतों के लिए थीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना है कि इन पदों को समाप्त करने का निर्णय प्रामाणिक रूप से लिया गया था। उन्होंने यह भी पाया कि छह याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियाँ अनियमित थीं और उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए था। हालाँकि, उन्होंने माना है कि जिस बोर्ड ने विचाराधीन प्रस्ताव पारित किया था, उसका गठन कानून के अनुसार नहीं किया गया था। इसलिए संकल्प का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। तदनुसार, उन्होंने रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के पदों को समाप्त करने वाले संकल्प को रद्द कर दिया है। उन्होंने यह भी देखा कि यह बोर्ड को कानून के अनुसार उचित बैठक आयोजित करने और रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के संबंध में उचित निर्णय लेने से नहीं रोकेगा। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बिना किसी स्पष्ट आदेश के अपीलों को खारिज कर दिया है। एकमात्र प्रश्न जिस पर हमें विचार करना है वह यह है कि क्या 14 मई, 1988 को निर्णय लेने वाला बोर्ड वैध रूप से गठित किया गया था। उस उद्देश्य के लिए, बिहार होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली विकास अधिनियम, 1953 की धारा 3 के प्रावधानों की ओर रुख करना आवश्यक है। धारा 3 इस प्रकार प्रदान करती हैः बोर्ड की स्थापना एवं गठन। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, बिहार राज्य होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड नामक एक बोर्ड की स्थापना कर सकती है जिसमें शामिल होंगेः

1. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक राष्ट्रपति,

2. राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले चार सदस्यय

3. पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा अपने बीच से निर्धारित तरीके से चुने जाने वाले सात सदस्य;

4. बिहार विधान सभा द्वारा इसके सदस्यों में से निर्धारित तरीके से चुने जाने वाले दो सदस्य; और

5. बिहार राज्य के लिए स्लेट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक एसोसिएशन या एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा निर्धारित तरीके से चुने जाने वाले दो सदस्य।

बशर्ते कि जब बोर्ड पहली बार स्थापित होए तो निवासी को खंड (ए) के तहत नामांकित किया जाएगा और सदस्यों को खंड (बी) के तहत नामित किया जाएगा और सदस्यों को खंड (सी), खंड (डी) के तहत चुना जाएगा। खंड (ई) या खंड (एफ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और इस प्रकार गठित बोर्ड धारा 6 के तहत आधिकारिक राजपत्र में अध्यक्ष और सदस्यों के नामों के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा तय की गई अतिरिक्त अवधि के लिए पद पर रहेगा। बोर्ड एक कॉर्पोरेट निकाय होगा और उसके पास स्थायी उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, जिसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति हासिल करने और रखने और निर्धारित शर्तों के अधीन ऐसी किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से मुकदमा दायर किया जा सकेगा। बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल धारा 5 द्वारा निर्धारित है जो इस प्रकार है। धारा 5– इस अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, दूसरे और प्रत्येक बाद के बोर्ड के नामांकित और निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल आधिकारिक राजपत्र में उनके नाम के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए होगा। 6 और इसमें कोई भी अतिरिक्त अवधि शामिल होगी जो तीन साल की उक्त अवधि की समाप्ति और सफल बोर्ड की पहली बैठक की तारीख, जिसमें कोरम मौजूद हैए के बीच हो सकता है। धारा 6 और 13 भी प्रासंगिक हैं. ये इस प्रकार हैंः

धारा 6– राष्ट्रपति और धारा 4 के तहत नामांकित या निर्वाचित किसी भी सदस्य के नाम राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

धारा 13–

1. बोर्ड का एक कार्यालय पटना में होगा और उसकी बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और बोर्ड की प्रत्येक बैठक ऐसे तरीके से बुलाई जाएगी जो विनियमों द्वारा प्रदान की जा सकती है; बशर्ते कि जब तक विनियम नहीं बन जाते, तब तक राष्ट्रपति के लिए यह वैध होगा कि वह पंद्रह दिनों के स्पष्ट नोटिस पर प्रत्येक सदस्य को संबोधित एक पत्र द्वारा ऐसे समय और स्थान पर परिषद की बैठक बुलाए, जिसे वह समीचीन समझे।

2. बोर्ड की किसी भी बैठक में तब तक कोई कामकाज नहीं किया जाएगा जब तक कि छह सदस्य उपस्थित न हों; बशर्ते कि किसी स्थगित बैठक में मूल बैठक में कोरम के अभाव में स्थगित किए गए सभी कार्यों को निपटाया जा सकता है, यदि ऐसी बैठक में कम से कम तीन सदस्य भाग लेते हैं।

इसलिए, बोर्ड एक मिश्रित निकाय है जो विभिन्न सदस्यों के समूह से बना है। बोर्ड के अध्यक्ष और चार सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना है। सात सदस्यों का चुनाव पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा किया जाना है। बिहार विधान सभा के दो सदस्यों को इसके सदस्यों में से चुना जाना है और दो सदस्यों को बिहार राज्य में मान्यता प्राप्त विभिन्न होम्योपैथिक संघों के सदस्यों द्वारा चुना जाना है। नामांकित या निर्वाचित होने पर सदस्यों के नाम अधिसूचित किए जाने चाहिए। 31 दिसंबर, 1982 की एक अधिसूचना के अनुसार, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार द्वारा एक बोर्ड अधिसूचित किया गया था जिसमें एक अध्यक्ष, चार नामांकित सदस्य और अन्य निर्वाचित सदस्य शामिल थे। अधिसूचना हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में दिए गए कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति और चार नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 31 जनवरी, 1983 से शुरू होना था और इसलिए, तीन साल के अंत में समाप्त हो जाएगा। 31 जनवरी 1986. सात निर्वाचित सदस्यों के नाम 17 अगस्त, 1984 को चुनाव होने के बाद ही अधिसूचित किए गए थे। 14 दिसंबर 1985 को विधान सभा के दो सदस्यों के नाम अधिसूचित किये गये। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि चूंकि सात निर्वाचित सदस्यों के नाम 17 अगस्त, 1984 को अधिसूचित किए गए थे, इसलिए उनका कार्यकाल 17 अगस्तए 1987 को ही समाप्त होगा। जबकि दो विधान सभा सदस्यों का कार्यकाल, जिन्हें 14 अगस्त, 1984 को अधिसूचित किया गया था, समाप्त हो जाएगा। दिसंबर, 1985, 14 दिसंबर, 1988 को समाप्त होगा। इसलिए, स्पष्ट रूप सेए बोर्ड एक समग्र निकाय है और इसके विभिन्न सदस्यों का कार्यकाल अलग–

अलग समय पर समाप्त होता है। इसलिए, बोर्ड की संरचना बदलती रहती है। चूंकि राष्ट्रपति और चार मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 31 जनवरी, 1986 को समाप्त हो रहा था, इसलिए 29 जनवरी, 1986 को एक नए राष्ट्रपति और चार नए मनोनीत सदस्यों को नामित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में यह भी निर्धारित किया गया है कि पिछले बोर्ड के वे सदस्य जिनकी नियुक्तियाँ दिनांक 17.8.1984 और 14.12.1985 की अधिसूचनाओं के तहत अधिसूचित की गई थीं; सात निर्वाचित सदस्य और विधान सभा के दो सदस्यद्ध तब तक नए बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे। वे तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। फरवरी 1986 के बाद, बोर्ड में एक नया अध्यक्ष, चार नए नामांकित सदस्य और मौजूदा सात निर्वाचित सदस्य और विधान सभा के मौजूदा दो सदस्य शामिल थे। इस बोर्ड की एक बैठक 14 मई 1988 को बुलाई गई थी, जब विचाराधीन पदों को समाप्त करने का बोर्ड प्रस्ताव पारित किया गया था। 14 मई 1988 को सात निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। हालाँकि, उन्हें सात नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया। 14 मई 1988 की बोर्ड बैठक में अध्यक्ष के अलावा तीन मनोनीत सदस्य एवं तीन निर्वाचित सदस्य उपस्थित थे। अपीलकर्ताओं के अनुसार, चूंकि किसी भी बोर्ड की बैठक के लिए कोरम छह है और अध्यक्ष के अलावा छह व्यक्ति उपस्थित थे, बोर्ड के पास कोरम था और वह व्यवसाय संचालित करने का हकदार था। सवाल यह है कि क्या धारा 5 के तहत, सात निर्वाचित सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि सात नए सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाते और उसके बाद बोर्ड की बैठक आयोजित की जाती, जिसमें कोरम पूरा होता। धारा 5 में प्रावधान है कि निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल तीन साल की अवधि के लिए होगा और अगले बोर्ड की पहली बैठक की तारीख तक तीन साल से अधिक की अवधि होगी, जिसमें कोरम मौजूद है। "सफल बोर्ड" से क्या तात्पर्य है? क्या इसका मतलब बोर्ड से उन सदस्यों को हटा देना है जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है? या क्या इसका मतलब निवर्तमान सदस्यों के स्थान पर नव निर्वाचित/नियुक्त सदस्यों वाला बोर्ड है, यह बाद वाला है जिसे "सफल बोर्ड" माना जा सकता है। बोर्ड एक समग्र निकाय है। यह सदस्यों के विभिन्न समूहों से बना है जो अलग-अलग निकायों द्वारा अलग-अलग तरीकों से नियुक्त या चुने जाते हैं। यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि सदस्यों के सभी समूह हमेशा एक ही समय में नामांकित या निर्वाचित होंगे। वास्तव में, इसे 29 जनवरी, 1986 की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई हैए जिसमें राष्ट्रपति और चार नामांकित सदस्यों को नए सिरे से नामित किया

गया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि सदस्यों के दो अन्य समूह, अर्थात् निर्वाचित सदस्य और विधान सभा सदस्य जिनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, वे भी बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे। इसलिए, सभी श्रेणियों के सदस्यों के लिए भी यही सच होगा। यदि पर्याप्त संख्या में सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो क्या शेष कुछ लोग केवल इसलिए बोर्ड के रूप में कार्य कर सकते हैं क्योंकि वे छह या अधिक हैं (कोरम का आंकड़ा)? ऐसी स्थिति से बचने के लिए, धारा 5 में सदस्यों को तब तक पद पर बने रहने का प्रावधान है जब तक कि आगामी बोर्ड का गठन नहीं हो जाता और वह कोरम के साथ बैठक नहीं कर लेता। धारा 5 का पहला भाग स्पष्ट रूप से बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है न कि बोर्ड के कार्यकाल की अवधि से। इसमें प्रावधान है कि सदस्यों का कार्यकाल आगामी बोर्ड की पहली बैठक (कोरम के साथ) तक जारी रहेगा। इसलिए, आगामी बोर्ड उन सदस्यों के बिना एक समाप्त बोर्ड का उल्लेख नहीं करता है जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। अगर यही मंशा होती तो बोर्ड की अगली बैठक तक पुराने सदस्य की सदस्यता जारी रखने का कोई मतलब नहीं होता, दो बैठकों के बीच के अंतराल में, चूंकि बोर्ड कोई कामकाज नहीं करता है, इसलिए पुराने सदस्यों को जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। तीन वर्ष की समाप्ति पर वे पद पर बने रहना भी बंद कर सकते हैं। उनके प्रतिस्थापित होने तक उन्हें जारी रखने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बोर्ड उचित रूप से गठित रहे। इसलिए, धारा 5 के संदर्भ में उत्तराधिकारी बोर्ड का मतलब केवल एक सफल बोर्ड हो सकता है जिसमें पुराने निवर्तमान सदस्यों का स्थान नए सदस्यों द्वारा लिया जाता है। एक बार जब उन्हें नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, और कोरम के साथ नए बोर्ड की बैठक होती है, तो सदस्यों का पिछला समूह बोर्ड का हिस्सा नहीं रह जाता है। वर्तमान मामले में, इसलिए, हालांकि अध्यक्ष और चार नामांकित सदस्य जनवरी, 1986 से बदल गए थे, बोर्ड के अन्य मौजूदा सदस्य बने रहे और अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक बने रहेंगे जब तक कि उन्हें सदस्यों के किसी अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। एक ही श्रेणी से संबंधित और कोरम के साथ बोर्ड की बैठक आयोजित की जा सकती है। इसलिए, सात निर्वाचित सदस्य जिनके नाम 17 अगस्त, 1984 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किए गए थे, वे अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी बोर्ड के सदस्य बने रहे क्योंकि उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था और कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वही बोर्ड जारी रहा. इसलिए, सात निर्वाचित सदस्य बोर्ड के सदस्य बने रहे

और 14 मई, 1988 को आयोजित बोर्ड की बैठक में भाग लेने के हकदार थे। चूंकि छह सदस्यों से कोरम बनता है, इसलिए बोर्ड की बैठक में अपेक्षित कोरम था और इसलिए, इसने वैध रूप से आठ पदों को समाप्त करने का एक प्रस्ताव पारित किया था। इसलिए, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही नहीं था कि 14 मई, 1988 का बोर्ड संकल्प एक विधिवत गठित बोर्ड द्वारा पारित नहीं किया गया था और इसलिए, इसे प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए। परिसर में, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है। तदनुसार मूल रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। फिर भी, उक्त पदों के पुनर्जीवित होने या भविष्य में इसी तरह के पद सृजित होने की स्थिति में बोर्ड छह मूल याचिकाकर्ताओं या उनमें से किसी एक या अधिक को उनकी पिछली सेवा को ध्यान में रखते हुए आयु में उपयुक्त छूट देकर ऐसे पदों पर नियुक्त करने पर विचार कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो बार, इन परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

प्रत्युष गुप्ता
न्यायाधिकारी ,
ग्राम न्यायालय, बिंदकी , फ़तेहपुर